

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING AND MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI H.K.L. BHAGAT) : (a) Construction of building for TV Relay Centre, Coimbatore is nearing completion and part of the equipment has been received at site.

(b) It is expected to be completed and commissioned by October this year.

(c) Installation of low power transmitters at Coimbatore, Kumbakonam and Neyveli is in progress and the centres are expected to be commissioned by October, '84.

Theft of Instruments and Equipment from Allahabad A.I.R.

3911. SHRI B.D. SINGH : Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state :

(a) whether it is a fact that several instruments and equipment were stolen from Allahabad station of All India Radio during the year 1982-83;

(b) whether it is also a fact that there is mismanagement at this station due to mutual differences among the officers;

(c) whether it is also a fact that Government had appointed an enquiry committee to go into all these things last year ;

(d) whether this enquiry committee has submitted its report to Government and if so, the main findings thereof; and

(e) whether Government have taken any action against the concerned officers so far and if so, details thereof ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI GHULAM NABI AZAD) : (a) 11 morots from old and unserviceable tape-decks were found to have been stolen. This was in May, 1982.

(b) No, Sir.

(c) to (e) A Police complaint was lodged. The report from the Police authority is still awaited. Taking action against these culpable would arise on the basis of such a report.

Meanwhile a departmental enquiry was conducted and the corrective measures/procedures recommended by the Inquiry Officer have also been adopted.

देश में श्रमिक न्यायालय/औद्योगिक न्यायाधिकरण

3912. श्री निहाल सिंह : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 31.7.1984 को श्रमिक न्यायालयों/औद्योगिक न्यायाधिकरणों की संख्या कितनी थी ;

(ख) देश में उपरोक्त तारीख को श्रमिक संघों और प्रबंधकों के बीच कितने औद्योगिक श्रम-विवाद लम्बित पड़े थे ;

(ग) उनमें से कितने मामले दो वर्षों से अधिक समय से लम्बित पड़े हैं ;

(घ) कितने मामले 3 वर्षों से अधिक समय से लम्बित पड़े हैं ; और

(ङ) इन मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल):

(क) केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालयों की संख्या दस है। उपलब्ध सूचना के अनुसार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 191 श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण और 6 औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय कार्य कर रहे हैं।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, 30.6.1984 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय सरकार

औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालयों के समक्ष 4,2(9 विवाद तथा 31.3.1983 को राज्य संघ राज्य क्षेत्रों औद्योगिक अधिकरणों/श्रम न्यायालयों के समक्ष 1,51,246 विवाद लंबित पड़े थे।

(ग) 43,857

(घ) 19,699

(ङ) केन्द्रीय सरकार ने चण्डीगढ़ और कानपुर में नए केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय स्थापित किए हैं। राज्य और संघ राज्य क्षेत्र भी, जब कभी आवश्यक समझते हैं, नए श्रम न्यायालय/अधिकरण स्थापित करते हैं। औद्योगिक विवाद (संशोधन) अधिनियम, 1982 में विवादों के समयबद्ध निपटान की व्यवस्था है। विवादों के निपटान के लिए मानदण्ड भी निर्धारित किए गए हैं।

बरेली और बदायूं जिलों में विद्युतीकृत गांवों की प्रतिशत और संख्या जिनका विद्युतीकरण किया गया है

3913. श्री जगपाल सिंह कश्यप : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बदायूं और बरेली जिलों में कितने प्रतिशत और कुल कितने गांवों का विद्युतीकरण किया गया है और कितने गांवों का अभी विद्युतीकरण किया जाना शेष है और तत्संबंधी पूर्ण म्योरा क्या है ; और

(ख) इन सभी गांवों का विद्युतीकरण कब तक किए जाने की सम्भावना है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) बदायूं और बरेली जिलों में कुल गांवों की संख्या विद्युतीकृत गांव (31.3.84 की स्थिति के अनुसार) तथा विद्युतीकरण की प्रतिशतता का स्तर और वे गांव जिन्हें अभी विद्युतीकृत किया जाना है के सम्बन्ध में स्थिति नीचे दिए गए अनुसार हैं :—

जिले	कुल गांवों की संख्या	की स्थिति के अनुसार विद्युतीकृत गांव	विद्युतीकरण का प्रतिशत स्तर	वे गांव जिन्हें अभी विद्युतीकृत किया जाना है।
1. बदायूं	1814	938	51.71	876
2. बरेली	1922	990	51.51	932

(ख) उत्तर प्रदेश में शत प्रतिशत विद्युतीकरण दसवें दशक के प्रारम्भ में हो जाने की आशा है बशर्ते इस बीच की अवधि में अपेक्षित निधियां उपलब्ध हों।

Piling up Stock, Capacity Utilization and Loss due to Rishikesh Unit in IDPL

3914. SHRI GEORGE FERNANDES ; Will the Minister of CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether heavy inventories are being built up by the IDPL;

(b) if so, the reasons therefore and the details of particular formulation that have contributed maximally to the huge inventories accumulated in the Antibiotics Plant, Rishikesh in the year 1984-85;

(c) the installed capacity of the IDPL and the capacity being utilised at present;